

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 2026 — चैत्र 25, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2026

क्रमांक 806/डी. 54/21-अ/प्रारू./छ.ग./26— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 06-04-2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2026.

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
2. परिभाषाएँ.

अध्याय-दो

प्रतिषेध और अपराध

3. अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध.
4. प्रश्नपत्र की अनधिकृत अभिरक्षा एवं प्रकटीकरण.
5. परीक्षा कार्य से संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण की रोकथाम.
6. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध.
7. परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का प्रयोग, लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जायेगा.
8. मूल्यांकन या अभिलेखों में हेराफेरी की रोकथाम.
9. प्रबंधन, संस्थान अथवा अन्य द्वारा किए गए अपराध.

अध्याय-तीन

अपराधों के लिए दंड

10. शास्ति.
11. अपराध के किए जाने में सहायता या सुविधा प्रदान करने के लिए दायित्व.
12. संपत्ति की समपहरण एवं कुर्की.
13. अधिनियम का अन्य विधियों के प्रतिकूल न होना

अध्याय-चार
जाँच और विवेचना

14. विवेचना हेतु सशक्त अधिकारी.

अध्याय-पाँच
विचारण और प्रक्रिया

15. अपराधों का विचारण एवं प्रक्रिया.

अध्याय-छः
प्रकीर्ण

- 16. लोकसेवक.
- 17. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.
- 18. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.
- 19. नियम बनाने की शक्ति.
- 20. अनुसूची में संशोधन की शक्ति.
- 21. परीक्षा संबंधी दस्तावेजों का उचित संधारण.
- 22. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

अनुसूची

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2026.

छत्तीसगढ़ राज्य में लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं से संबंधित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के रोकथाम करने तथा उससे संबद्ध या आनुसंगिक विषयों के उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

- | | |
|--|--|
| <p>1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2026 कहलाएगा।</p> <p>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।</p> <p>(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें।</p> | <p>संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ.</p> |
| <p>2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-</p> <p>(क) "अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत उसकी ओर से लेखक या सहायक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;</p> <p>(ख) "संसूचना उपकरण" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (जक) में उसके लिए यथा समनुदेशित है;</p> <p>(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य शासन का वह विभाग, जो लोक परीक्षा प्राधिकरण के प्रशासनिक</p> | <p>परिभाषाएँ.</p> |

रूप से प्रभार में हो;

- (घ) "कंप्यूटर नेटवर्क", "कंप्यूटर साधन" तथा "कंप्यूटर प्रणाली" के वही अर्थ होंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ज), (ट) एवं (ठ) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है;
- (ङ) "लोक परीक्षा का संचालन" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं सभी प्रक्रियाएं, चरण एवं गतिविधियां, जिन्हें लोक परीक्षाओं के संचालन हेतु अपनाया जाना हो, जिसमें प्रश्नपत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं, ओ.एम.आर. पत्रकों, परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं संकलन, स्कैनिंग, मूल्यांकन एवं परिणाम की घोषणा भी सम्मिलित है;
- (च) "परीक्षा केन्द्र" से अभिप्रेत है, कोई संस्था अथवा उसका भाग या ऐसा कोई अन्य स्थान, जिसे लोक परीक्षा के आयोजन हेतु निर्धारित एवं प्रयुक्त किया गया हो तथा उसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर भी सम्मिलित होंगे;
- (छ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
- (ज) "संस्थान" से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों के संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, साझेदारी या एकल स्वामित्व फर्म, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, जो लोक परीक्षा प्राधिकरण से भिन्न है तथा इसमें ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता शामिल है;
- स्पष्टीकरण:** इस खंड के प्रयोजन हेतु, "कंपनी" में सम्मिलित हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 18) की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2008 का सं. 6) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी फर्म।
- (झ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

- (ज) "संगठित अपराध" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा लोक परीक्षा के संबंध में अनुचित लाभ हेतु किसी साझा हित को आगे बढ़ाने या बढ़ावा देने के षडयंत्र तथा दुरभिसंधि में अनुचित साधनों का प्रयोग करना;
- (ट) "सेवा प्रदाता से संबद्ध व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो उस सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवाएं प्रदान करता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह व्यक्ति यथास्थिति, कर्मचारी या अभिकर्ता अथवा ऐसे सेवा प्रदाता का सहायक हो;
- (ठ) "लोक परीक्षा" से अभिप्रेत है, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित परीक्षा अथवा ऐसी अन्य परीक्षा जो राज्य शासन द्वारा शासकीय राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित की जाये;
- स्पष्टीकरण-** छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2008 की धारा 2 (ग) के अधीन अनुसूची में अधिसूचित कोई भी लोक परीक्षा, उक्त अधिनियम के अधीन ही शासित होती रहेगी।
- (ड) "लोक परीक्षा प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकरण अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण, जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो;
- (ढ) "लोक सेवा" से अभिप्रेत है, शासन के किसी भी कार्यालय या स्थापनाओं, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य शासन के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगम या उपक्रम, राज्य विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्थापित निकाय, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं (जिसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं) तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य निकाय;
- (ण) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची;
- (त) "सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है, किसी अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों के संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, साझेदारी या एकल स्वामित्व फर्म, जिसमें उसके

सहायक, उप-ठेकेदार तथा किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी सामग्री के सहायक प्रदाता सम्मिलित हैं, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा लोक परीक्षा के संचालन हेतु संलग्न किया गया हो;

(थ) "पर्यवेक्षण कर्मचारी" में सम्मिलित हैं, ऐसे व्यक्ति, जिन्हें आयोजित लोक परीक्षा में लोक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(द) "अनुचित साधन" किसी लोक परीक्षा के संबंध में अभिप्रेत है, ऐसा कोई कार्य या लोप, जिसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं द्वारा मौद्रिक या अनुचित लाभ के लिए किया गया हो या करवाया गया हो तथा जिसमें निम्नलिखित कृत्य सम्मिलित हैं, किन्तु वे इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, अर्थात:-

(एक) परीक्षार्थी के संबंध में:

- (1) किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई अनधिकृत सहायता प्राप्त करना;
- (2) किसी भी रूप में लिखित, रिकॉर्ड की गई, नकल की गई, मुद्रित या पुनरुत्पादित सामग्री का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना;
- (3) किसी भी दूरसंचार, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या अन्य उपकरण अथवा यंत्र का अनधिकृत प्रयोग करना;
- (4) परीक्षा कक्ष में शरीर, वस्त्र, फर्नीचर, फिक्सचर या अन्य किसी वस्तु पर जानबूझकर कोई चिन्ह, संकेत, शब्द, संख्या या छाप अंकित करना उत्कीर्ण करना या नक्काशी, जो अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त हो सके।

(दो) किसी व्यक्ति (जिसमें अभ्यर्थी भी सम्मिलित है) के संबंध में:

- (1) किसी अभ्यर्थी का प्रतिरूप धारण करना या उसका प्रयास करना;
- (2) प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग का प्रकटीकरण करना, करने का प्रयास

- करना या षड्यंत्र करना;
- (3) प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (OMR) उत्तर पत्रक को अनधिकृत रूप से प्राप्त करना या उस पर अधिकार प्राप्त करना;
 - (4) किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रश्नों का उत्तर देना या समाधान प्रदान करना;
 - (5) किसी अभ्यर्थी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनधिकृत रूप में सहायता प्रदान करना;
 - (6) उत्तर पुस्तिकाओं, जिसमें OMR पत्रक भी सम्मिलित हैं, से छेड़छाड़ करना;
 - (7) मूल्यांकन या अंक परिवर्तन करना, सिवाय इसके कि किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारा जा रहा हो और वह भी बिना वैध प्राधिकार के;
 - (8) राज्य शासन द्वारा लोक परीक्षाओं के संचालन हेतु निर्धारित किन्हीं नियमों, मानकों या मापदंडों का जानबूझकर उल्लंघन करना;
 - (9) मेरिट अथवा रैंक निर्धारण हेतु आवश्यक दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना;
 - (10) सुरक्षा प्रोटोकॉल या उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना;
 - (11) परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित किसी कंप्यूटर नेटवर्क, प्रणाली या संसाधन से छेड़छाड़ करना;
 - (12) बैठने की व्यवस्था, परीक्षा तिथियों या पालियों/पेपर के आवंटन में हेराफेरी करना;
 - (13) परीक्षा के संचालन में परीक्षा प्राधिकरण, सेवा प्रदाता या अधिकृत अभिकरण से संबद्ध किसी व्यक्ति को धमकाना, अनुचित रूप से रोकना, या बाधा डालना;
 - (14) धोखाधड़ी या अवैध लाभ के उद्देश्य से नकली वेबसाइट का निर्माण या संचालन करना;
 - (15) नकली परीक्षा आयोजित करना या नकली

प्रवेश पत्र या नियुक्ति पत्र जारी करना;

- (16) वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के आशय से परीक्षा से पूर्व, नकली प्रश्नपत्र को वास्तविक बताकर वितरित करना अथवा प्रसारित करना।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो यहां प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में उनके लिए यथा समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

प्रतिषेध और अपराध

3. (1) किसी भी लोक परीक्षा में अथवा उसके संबंध में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करना प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थान इस प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए आपस में मिलीभगत या षड्यंत्र रचने का कार्य नहीं करेगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी अपराध, इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के प्रयास या उसके दुष्प्रेरण को भी सम्मिलित करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति, जिसे उसके कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक अधिकृत नहीं किया गया है या अनुमति नहीं दी गई है, वह किसी लोक परीक्षा में परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र छोड़ने के निर्धारित समय से पूर्व अथवा प्रश्न पत्रों को खोलने एवं वितरण हेतु निर्धारित समय से पूर्व:
 - (क) ऐसे प्रश्नपत्र अथवा उसके किसी भाग या प्रति को किसी भी प्रकार से प्राप्त करने, प्राप्त करने या अपने पास रखने का प्रयास नहीं करेगा; अथवा
 - (ख) ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा या उसकी पेशकश नहीं करेगा, जिसके बारे में उसे ज्ञान है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह जानकारी ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित है, उससे व्युत्पन्न है, अथवा उस पर प्रभाव डालती है।
5. कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य

**अनुचित साधनों
के उपयोग का
प्रतिषेध.**

**प्रश्नपत्र की
अनधिकृत
अभिरक्षा एवं
प्रकटीकरण.**

परीक्षा कार्य से

सौंपा गया है, वह, जब तक कि उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन की दृष्टि से वैध रूप से ऐसा करने की अनुमति प्राप्त न हो, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी जानकारी या उसका अंश, जो उसके संज्ञान में उसे सौंपे गये कार्य के कारण आया है, अनुचित लाभ या किसी गलत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रकट नहीं करेगा अथवा प्रकट करने का कार्य नहीं करेगा।

संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण की रोकथाम.

6. कोई भी व्यक्ति, जो लोक परीक्षा के कार्य से संबद्ध या लोक परीक्षा संचालन हेतु संलग्न अथवा न्यस्त नहीं है अथवा परीक्षार्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया में बाधा या व्यवधान डालने के आशय से परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
7. कोई भी व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त या संलग्न किया गया है, वह लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना, परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन से, परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा:

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध.

परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का प्रयोग, लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जायेगा.

परंतु यह कि, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, अपराध का गठन नहीं करेगी जहाँ परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, दंगा इत्यादि या इसी तरह की घटनाओं सहित अपरिहार्य परिस्थितियों (फोर्स मेज्योर) के कारणवश आवश्यक हो जाए और जिसे बाद में लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, परीक्षा केन्द्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया हो।

8. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन अथवा ऐसे मूल्यांकन के अभिलेखों के साथ किसी प्रकार की हेराफेरी या हेराफेरी का प्रयास नहीं करेगा।

मूल्यांकन या अभिलेखों में हेराफेरी की रोकथाम.

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'मूल्यांकन अभिलेख' में उत्तर पुस्तिकाएँ, टैबुलेशन शीट्स, अंक पंजिका, व्यक्तिगत अंक तालिकाएँ, परिणाम पत्रक या उनकी प्रतियाँ अथवा इस प्रयोजन हेतु बनाई गई कोई अन्य पंजी या अभिलेख सम्मिलित होंगे।

9. (1) जहाँ इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी, संस्था, फर्म, सोसाइटी, सीमित दायित्व

प्रबंधन, संस्थान

साझेदारी या व्यक्तियों के संघ द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित होते समय, उसके कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी और प्रभारी हो साथ ही वह संस्था भी स्वयं उस अपराध के लिए अभियोजन के उत्तरदायी होगी।

**अथवा अन्य
द्वारा किए गए
अपराध.**

- (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरायेगी, यदि वह सिद्ध कर देता है कि उक्त अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा उसने उसे रोकने के लिए यथासंभव सावधानी बरती थी।
- (3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा अपराध किसी निकाय द्वारा उसके किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौन स्वीकृति अथवा उनकी ओर से की गई किसी उपेक्षा से किया गया है, तो वह व्यक्ति भी अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय-तीन

अपराधों के लिए दंड

10. (1) अभ्यर्थी द्वारा अपराध किये जाने की दशा में,-

शास्ति.

धारा 3 का उल्लंघन करने वाले किसी भी अभ्यर्थी का परिणाम रोक जाएगा तथा उसे लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा ऐसी लोक परीक्षा में सम्मिलित होने से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिये, जो अधिकतम आगामी तीन कैलेंडर वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है, प्रतिबंधित किया जायेगा:

परंतु यह कि ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, उक्त प्रतिबंध उन्हे किसी भी लोक परीक्षा अथवा लोक सेवा में सम्मिलित होने से अयोग्य नहीं ठहरायेगा।

(2) अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किये जाने की दशा में,-

(क) जो कोई धारा 3 का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी और जुर्माना जो अधिकतम दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

(ख) जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 या धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या ऐसे उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसके उल्लंघन का षडयंत्र करेगा अथवा ऐसे उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो पाँच वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी और जुर्माना जो अधिकतम पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, सेवा प्रदाताओं, संस्थानों एवं प्रबंधन के द्वारा किये गये अपराध की दशा में,-

(क) कोई सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के लिये उत्तरदायी होगा तथा ऐसे सेवा प्रदाता से परीक्षा की आनुपातिक लागत की वसूली भी की जाएगी। साथ ही, उसे किसी भी लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी सौंपे जाने से, ऐसी अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

(ख) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता फर्म या संस्थान के किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन अथवा प्रभारी व्यक्ति की सहमति या मौन स्वीकृति से किया जाना स्थापित होता है, तो वह ऐसे कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो एक करोड़ रुपये तक हो सकेगा, के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) उप-धारा (1), (2) एवं (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह (जिसमें परीक्षा प्राधिकरण, सेवा प्रदाता, कोई अन्य संस्था अथवा

कोई अभ्यर्थी सम्मिलित है) संगठित अपराध करता है, वे ऐसे कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, से दंडित किया जायेगा।

जुर्माने के भुगतान में चूक होने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (क्र. 45 सन् 2023) के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त कारावास का दंड भी अधिरोपित किया जायेगा।

(ख) यदि कोई संस्थान या सेवा प्रदाता, संगठित अपराध करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 (क्र. 45 सन् 2023) के उपबंधों के अनुसार कुर्की एवं समपहरण के अधीन होगी तथा उससे परीक्षा की अनुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी।

11. जो कोई, किसी मौद्रिक सहायता प्रदान करके अथवा किसी भवन, परिसर, सुविधा या अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, संस्थान या सेवा प्रदाता को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किये जाने में सहायता या सुविधा प्रदान करता है, उसके संबंध में, जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसे ऐसे अपराध या उसके आशयित कृत्य का ज्ञान था और उसे अपराध का कर्ता माना जाएगा तथा मुख्य अपराधी के समान ही दंड का उत्तरदायी होगा।
12. (1) संपत्ति की कुर्की तथा समपहरण के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र. 46 सन् 2023) के उपबंध, यथासंभव, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।
(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी दंड के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी ऐसे दोषसिद्ध अथवा उत्तरदायी पाये गये व्यक्ति से परीक्षा के संचालन में व्यय की गई आनुपातिक लागत की वसूली कर सकेगा।
13. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

अपराध के किए जाने में सहायता या सुविधा प्रदान करने के लिए दायित्व.

संपत्ति की जब्ती एवं समपहरण.

अधिनियम का अन्य विधियों के प्रतिकूल न होना.

अध्याय-चार जांच और विवेचना

14. (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी अपराध का अन्वेषण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो उप पुलिस निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो।
- (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अन्वेषण को किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अन्वेषण एजेंसी को सौंप सके।

**विवेचना हेतु
सशक्त
अधिकारी.**

अध्याय-पाँच विचारण और प्रक्रिया

15. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र4 .6 सन् (2023 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

**अपराधों का
विचारण एवं
प्रक्रिया.**

अध्याय-छः प्रकीर्ण

16. लोक परीक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यगण, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी तथा प्रत्येक वह व्यक्ति, जो किसी लोक परीक्षा के संचालन में संलग्न हो, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में, कार्य करते हुए अथवा ऐसा करने का प्रयत्न करते हुए, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का सं. 45) के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।
17. इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य, जो सद्भावनापूर्वक किया गया हो या किया जाना आशयित हो, उसके लिए सरकार या किसी अधिकारी या सरकार के प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी:

लोक सेवक.

**सद्भावनापूर्वक
की गई कार्यवाही
के लिए संरक्षण.**

परंतु, ऐसे लोक सेवक जिनके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपराध किये जाने का प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान हो, तब उसे कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

18. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

**अधिनियम का
अध्यारोही प्रभाव.**

19. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

**नियम बनाने की
शक्ति.**

विशेष रूप से, उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में बना सकेगी, अर्थात्:-

(एक) लोक परीक्षा के संचालन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं, कार्यप्रणाली तथा गतिविधियों का निर्धारण;

(दो) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना हो अथवा विहित किया जाये।

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गये सभी नियमों को, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

20. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करते हुए उसमें नये परीक्षा प्राधिकरणों या लोक परीक्षाओं को जोड़ सकेगी या उनमें से किसी को हटा सकेगी तथा इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा अनुसूची की प्रविष्टियों में संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी।

**अनुसूची में
संशोधन की
शक्ति.**

- (2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक ऐसी अधिसूचना को, यथाशीघ्र सम्भव हो, राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

21. लोक परीक्षा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा की लोक परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा, समुचित रखरखाव तथा सुव्यवस्थित संधारण किया जायेगा।

परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण संबंधित परीक्षा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक किया जाएगा।

22. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत ना हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक आदेश, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

परीक्षा संबंधी
दस्तावेजों का
उचित संधारण.

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति.

अनुसूची

[धारा 2(1)(ठ) एवं (ड) देखिए]

छत्तीसगढ़ में लोक परीक्षा प्राधिकरण एवं लोक परीक्षाएँ

स.क्र.	लोक परीक्षा प्राधिकरण	लोक परीक्षाएँ
(1)	(2)	(3)
1.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग	लोक सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित सभी परीक्षाएँ।
2.	छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल	(1) लोक सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित सभी परीक्षाएँ। (2) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित सभी परीक्षाएँ।
3.	राज्य सरकार के विभाग तथा उनके संलग्न एवं अधिनस्थ कार्यालय, जिनमें राज्य के सार्वजनिक उपक्रम भी सम्मिलित हैं	लोक सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित सभी परीक्षाएँ।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2026

क्रमांक 806/डी. 54/21-अ/प्रारू./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों) की रोकथाम अधिनियम, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No 3 of 2026)

**THE CHHATTISGARH (PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN PUBLIC
RECRUITMENT AND PROFESSIONAL EXAMINATIONS) ACT, 2026.****CONTENTS****Section****CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

**CHAPTER-II
PROHIBITIONS AND OFFENCES**

3. Prohibition of the use of unfair means.
4. Unauthorised possession and disclosure of question paper.
5. Prevention of leakage by person entrusted with examination work.
6. Prohibition on entry into examination centre.
7. No place other than examination centre shall be used for public examination.
8. Prevention of manipulation of evaluation or record.
9. Offences by Management, Institution or others.

**CHAPTER-III
PUNISHMENT FOR OFFENCES**

10. Penalties.
11. Liability for aiding or facilitating the commission of offence.
12. Forfeiture and Attachment of Property.
13. Act not in derogation of other laws.

**CHAPTER-IV
INQUIRY AND INVESTIGATION**

14. Officers empowered to investigate.

CHAPTER-V

TRIAL AND PROCEDURE

15. Trial and Procedure for offences.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

16. Public Servant.

17. Protection of action taken in good faith.

18. Overriding effect of Act.

19. Power to make rules.

20. Power to amend Schedule.

21. Proper maintenance of examination related documents.

22. Power to remove difficulties.

SCHEDULE

CHHATTISGARH ACT

(No 3 of 2026)

THE CHHATTISGARH (PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN PUBLIC RECRUITMENT AND PROFESSIONAL EXAMINATIONS) ACT, 2026.

An Act to prevent unfair means in the public examinations related to recruitment and professional examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I PRELIMINARY

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <p>(1) This Act may be called the Chhattisgarh (Prevention of Unfair Means in Public Recruitment and Professional Examinations) Act, 2026.</p> <p>(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.</p> <p>(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoints.</p> | <p>Short title,
extent and
commencement.</p> |
| 2. | <p>(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) "Candidate" means a person who has been granted permission by the public examination authority to appear in a public examination and includes a person authorized to act as a scribe or assistant on their behalf;</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) "Communication Device" shall have the same meaning as assigned to it in clause (ha) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000);</p> <p style="padding-left: 20px;">(c) "Competent Authority" means the Department of the State Government administratively in charge of the public examination authority;</p> | <p>Definitions.</p> |

(d) "**Computer Network**", "**Computer Resource**" and "**Computer System**" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (j), (k) and (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000);

(e) "**Conduct of Public Examination**" shall mean and include all the procedures, processes, and activities being adopted for the conduct of public examination, including preparation, printing, supervision, coding, processing, storing, transportation, distribution and collection of question papers, answer sheets, OMR sheets, result sheets, scanning, evaluation and declaration of result;

(f) "**Examination Centre**" means any institution or part thereof or any other place fixed and used for holding of a public examination and shall include the entire premises attached thereto;

(g) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(h) "**Institution**" means any agency, organization, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, by whatever name it may be called, which is other than the public examination authority and includes any service provider engaged by such authority;

Explanation- For the purposes of this clause, "company" includes a company as defined in clause (20) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013); or a limited liability partnership firm as defined in clause (n) of sub-section (1) of Section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (No. 06 of 2009).

(i) "**Notification**" means a notification published in the Official Gazette and the word 'notified' shall

be construed accordingly;

- (j) **"Organized Crime"** means an unlawful activity committed by a person or a group of persons indulging in unfair means in collusion and conspiracy to pursue or promote a shared interest for wrongful gain in respect of a public examination;
- (k) **"Person Associated with a Service Provider"** means a person who performs services for or on behalf of such service provider irrespective of the fact that whether such person is an employee or an agent or a subsidiary of such service provider, as the case may be;
- (l) **"Public Examination"** means any examination as specified in the Schedule or any other examination as may be notified by the State Government in the Official Gazette from time to time.

Explanation- Any public examination notified in the Schedule under Section 2(c) of the Chhattisgarh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2008 shall continue to be governed under the said Act;

- (m) **"Public Examination Authority"** means an examination authority as specified in the Schedule or such other authority as may be notified by the State Government in the Official Gazette from time to time;
- (n) **"Public Service"** means services in any office or establishments of the Government, a local authority, a Corporation or undertaking owned or controlled by the State Government, a body established under any law made by the Legislature of the State whether incorporated or not (including a University), and any other body established by the State Government;
- (o) **"Schedule"** means the Schedule appended to this Act;
- (p) **"Service Provider"** means any agency, organization, body, association of persons, business entity, company, partnership or sole

proprietorship firm, including its associates, sub-contractors and provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination.

(q) **"Supervisory Staff"** includes persons authorized by the examination authority to conduct public examination;

(r) **"Unfair Means"** in relation to a public examination, means any act or omission done or caused to be done by any person or group of persons or institutions, including but not restricted to the following acts, for monetary or wrongful gain; namely:-

(i) In relation to candidate,-

- (1) receiving, whether directly or indirectly, any unauthorized assistance from any person;
- (2) using or attempting to use, in any form, any written, recorded, copied, printed, or reproduced material;
- (3) unauthorized use of any telecommunication, wireless, electronic, mechanical, or other device or apparatus;
- (4) knowingly marking, inscribing, or engraving any sign, symbol, word, number or imprint on the body, clothing, furniture, fixtures, or any other object in the examination hall which may be used for obtaining undue advantage.

(ii) In relation to any person (including candidate),-

- (1) impersonating candidate or attempting to do so;
- (2) leaking, attempting to leak, or conspiring to leak a question paper, answer key, or any part thereof;
- (3) unauthorized acquisition or possession of the question paper or

Optical Mark Recognition (OMR)
answer sheet;

- (4) Providing answers or solutions to questions by any unauthorized person;
 - (5) providing, whether directly or indirectly, unauthorized assistance to any examinee;
 - (6) tampering with answer scripts, including OMR sheets;
 - (7) altering the evaluation or marks awarded, except for the correction of a genuine error and that too without valid authorisation;
 - (8) willfully violating any regulations, instructions, guidelines, standards or criteria specified by the public examination authority for the conduct of public examination.
 - (9) tampering with documents required for the determination of merit or rank;
 - (10) willful breach of security protocols or measures;
 - (11) tampering with any computer network, system, or resource related to the examination process;
 - (12) manipulating seating arrangements, examination dates, or allocation of shifts/papers;
 - (13) threatening, unlawfully restraining or obstructing any person associated with the examination authority, service provider or authorized agency in the conduct of the examination;
 - (14) creating or operating a fake website with the intent to defraud or derive unlawful gain;
 - (15) conducting a fake examination or issuing fake admit cards or appointment letters;
 - (16) circulating or distributing a fake question paper before the examination by falsely representing it as genuine, with the intent to obtain financial or material gain.
- (2) Words and expressions used herein but not defined and defined under any other law for the time being in force, shall have the same

meanings as assigned to them in those laws.

CHAPTER-II

PROHIBITIONS AND OFFENCES

- | | | |
|----|--|--|
| 3. | <p>(1) The use of unfair means at or in connection with any public examination by any person or group of persons or institutions is hereby prohibited. No person, or group of persons, or institutions shall collude or conspire to facilitate the commission of any such unfair means.</p> <p>(2) Any offence committed under this Act shall include the attempt or abetment to commit such offence under this Act.</p> | <p>Prohibition of the use of unfair means.</p> |
| 4. | <p>No person, who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do, shall before the time fixed for the examinees to leave an examination centre at a public examination or before the time fixed for opening and distribution of question papers:</p> <p>(a) procure or attempt to procure or possess, such question paper or any portion or a copy thereof by any means; or</p> <p>(b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe, to be related to or derived from or to have a bearing upon such question paper.</p> | <p>Unauthorised possession and disclosure of question paper.</p> |
| 5. | <p>No person, who is entrusted with any work pertaining to a public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him, for any undue advantage or wrongful gain.</p> | <p>Prevention of leakage by person entrusted with examination work.</p> |

- | | | |
|----|---|---|
| 6. | No person, not entrusted or engaged with the work pertaining to a public examination or conduct of public examination or who is not candidate, shall enter into the premises of the examination centre with intent to interfere with, obstruct or disrupt the conduct of the public examination. | Prohibition on entry into examination centre. |
| 7. | <p>No person, who is entrusted or engaged with the work pertaining to a public examination shall use or cause to be used any place, other than the examination centre, for the purpose of holding a public examination, without the written approval of the public examination authority:</p> <p>Provided that, nothing contained in this section shall constitute an offence where any change in the examination centre, is necessitated due to force majeure circumstances, including natural calamity, war, riot or similar events and is subsequently notified as Examination Centre by the Public Examination Authority.</p> | No place other than examination centre shall be used for public examination. |
| 8. | <p>No person shall directly or indirectly indulge or involve in any manipulation or attempted manipulation of the evaluation of the performance of candidate at a public examination or the record of such evaluation.</p> <p>Explanation- For the purposes of this section, the expression 'record of evaluation' includes answer scripts, tabulation sheets, marks registers, individual mark sheets, result sheets or the copies thereof or any other registers or records maintained in this behalf.</p> | Prevention of manipulation of evaluation or record. |
| 9. | (1) Where an offence under any of the provisions of this Act has been committed by a company, institution, firm, society, limited liability partnership, or other association of individuals, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of and responsible for the conduct of its business, as well as the entity itself, shall be liable to be prosecuted. | Offences by Management, Institution or others. |

(2) Nothing in sub-section (1) shall render any such person liable to punishment if they prove that the offense was committed without their knowledge or that they exercised all due diligence to prevent its commission.

(3) Notwithstanding anything in sub-section (1), if such an offence is committed by an entity with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, partner, manager, secretary, or any other officer, such individual shall also be liable to be prosecuted.

CHAPTER-III PUNISHMENT FOR OFFENCES

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 10. | <p>(1) In case of offence committed by candidate.-
Any candidate contravening Section 3, shall have their result withheld and be debarred by the public examination authority from appearing in such public examination for not less than one year but which may extend up to three subsequent calendar years:
Provided that, such debarment shall not disqualify them from appearing in any public examination or public service after the debarment period.</p> <p>(2) In case of offence committed by Person other than the candidate.-
(a) Whoever contravenes Section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend up to ten years, and with fine maximum up to rupees ten lakh.
(b) Whoever contravenes or attempts or conspires to contravene or abets the contravention of the provisions of Section 4 or Section 5 or Section 6 or Section 7 or Section 8 or Section 9 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend up to five years, and with a fine maximum up to rupees five lakh.</p> | <p>Penalties.</p> |
|-----|---|--------------------------|

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), In case of offence committed by Service Providers, Institutions, and Management:-

(a) A service provider shall be liable to be punished with a fine up to one crore rupees, and the proportionate cost of the examination shall also be recovered from such service provider. They shall also be barred from being assigned with any responsibility for the conduct of any public examination for a period not less than three years.

(b) Where an offence under this Act is established to have been committed with the consent or connivance of any Director, Senior Management, or persons in charge of the service provider firm or institution, they shall be liable for imprisonment for a term not less than three years but which may extend upto ten years and with a fine upto one crore rupees.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) and (3),

(a) If a person or a group of persons (including the examination authority, service provider, any other institution, or a candidate) commits an organized crime, they shall be punishable with imprisonment for a term not less than three years but which may extend upto five years and with fine which shall not be less than one crore rupees.

In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023).

(b) If an institution or service provider is involved in committing an organized crime, it's property shall be subjected to attachment and forfeiture as per the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), and proportionate cost of examination shall also be recovered from it.

- | | | |
|-----|--|--|
| 11. | Whoever, by providing any monetary assistance, or by making available any building, premises, facility, or other resources, aids or facilitates any individual, group of individuals, institution or service provider in the commission of an offence under this Act, shall be presumed, unless the contrary is proved, to have had the knowledge of such offence or its intended commission, and shall be deemed to have committed that offence and shall be liable to the same punishment as the principal offender. | Liability for
aiding or
facilitating the
commission of
offence. |
| 12. | <p>(1) The provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), relating to attachment and forfeiture of property shall, so far as may be, apply for the purposes of this Act.</p> <p>(2) In addition to any penalty imposed under this Act, the competent authority may recover from the person so convicted or found responsible, the proportionate cost incurred in conducting the examination.</p> | Forfeiture and
Attachment of
Property. |
| 13. | The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force. | Act Not in
Derogation of
Other Laws. |

CHAPTER-IV INQUIRY AND INVESTIGATION

- | | | |
|-----|---|---|
| 14. | <p>(1) An officer not below the rank of Sub-Inspector of Police shall investigate any offence committed under this Act.</p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government shall have the powers to refer the investigation to any Central or State Investigating Agency.</p> | Officers
Empowered to
Investigate. |
|-----|---|---|

CHAPTER-V TRIAL AND PROCEDURE

15. Offences under this Act shall be triable in accordance with the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023).

**Trial and
Procedure for
offences.**

CHAPTER-VI MISCELLANEOUS

16. The Chairperson, Members, officers, and other employees of the public examination authority, and every person engaged in the conduct of a public examination, shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be Public Servant within the meaning of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023).

**Public
Servant.**

17. No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer or authority of Government or any other person for anything which is done in good faith or intended to be done under this Act or the rules or orders made there under:

**Protection
of action
taken in
good faith.**

Provided that nothing shall prevent proceeding against such public servants where, a prima facie case exists for establishing the commission of an offence under this Act.

18. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

**Overriding
effect of the
Act.**

19. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

**Power to
make Rules.**

In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (i) To lay down procedures, processes and activities for being adopted for conduct of a

public examination;

(ii) Any other matter which is to be or may be prescribed.

(2) All the rules made under this Act shall, be laid before the Legislative Assembly of the State as soon as it may be so possible.

20. (1) The State Government by notification published in the Official Gazette may amend the Schedule of the Act to add new Examination Authorities or Public Examinations or remove any of them and may by like notification amend or vary the entries of the schedules.

**Power to
amend
Schedule.**

(2) Every such notification issued under this section by the State Government shall be laid before the State Legislative Assembly as soon as it may be so possible.

21. The Public Examination Authority shall ensure the secure custody, proper upkeep, and orderly retention of all records relating to a public examination.

**Proper
maintenance
of
examination
related
documents.**

All records connected with the examination shall be retained for the period as specified by concerned examination authority.

22. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with this Act, as may appear it to be necessary or expedient for removal of difficulty:

**Power to
remove
difficulties.**

Provided that, no such power shall be exercise after expiry period of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order issued under this section by the State Government shall be laid before the State Legislative Assembly.

SCHEDULE

[See Sections 2(1)(i) and (m)]

Public Examination Authorities and Public Examinations in Chhattisgarh

S. No.	Public Examination Authority	Public Examinations
(1)	(2)	(3)
1.	Chhattisgarh State Public Service Commission	All examinations for selection of candidates for Public Services.
2.	Chhattisgarh Professional Examination Board	1. All examinations for selection of candidates for Public Services. 2. All examinations for professional courses.
3.	Departments of the State Government and their attached and subordinate offices, including state public sector undertakings	All examinations for selection of candidates for Public Services.